सहकारिता क्षेत्र में बिजली करघा उद्योग को सहायता

2451. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों द्वारा सहकारिता क्षेत्र में संचालित बिजली-करघा उद्योग के संरक्षण हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता देना जारी रखा जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक" तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विभिन्न सहकारी संस्थाओं/व्यवसायिक बैंकों/राज्य वित्त निगमों की मार्फत सहकारी विद्युत करघों को आवधिक ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों ही उपलब्ध करने के लिए पुनर्वित्त प्रदान करते हैं।

हथकरघा बुनकरों को राहत

2452. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए सरकार बुनकरों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार "यार्न प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड" के लिए योगदान करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार राज्यों में पोलिएस्टर प्रोसेसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है ताकि हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाये गए वस्त्रों को राज्यों में ही संसाधित किया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने यार्न की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) स्टेपल काटन का निर्यात स्थगित कर दिया गया है ;

(2) 60 काउन्टो तक के हैंक यार्न का निर्यात स्थगित कर दिया है ;

(3) अग्रिम लाइसेंस के आधार पर सूती यार्न/सूती फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स के निर्यात के बदले रूई के आयात की अनुमति दी गई है ; तथा

(4) हथकरघा क्षेत्र को सप्लाई के लिए हैंक यार्न के उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त रूई की एक लाख गांठ के आयात की अनुमति दी गई है।

(ख) केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केन्द्र सरकार हथकरघा क्षेत्र में करघापूर्व तथा करघा पश्चात प्रोसेसिंग की प्रक्रिया संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रही है। योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा पोलिएस्टर कपड़े की प्रोसेसिंग के लिए सुविधाओं हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिलें

2453. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) तथा (ख) सातवी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान

मध्य प्रदेश में किसी भी नई सहकारी कताई मिल की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

Nationalisation of Swadeshi Cotton Mills

2454. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether he has seen reports in the *Nava Bharat Times* of July 1, July 20 and July 24, 1988 stating that in the Financial Memorandum attached to the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill, 1986 reference or information regarding the loan of Rs. 35 crores was left out and this amount of Rs. 35 crores has been written-off without initiating any recovery measures against the owners of the Mill, if so, what are the details thereof;

(b) whether Swadeshi polytex Limited has recently incurred a loss; if so, by how much and will it be a sick mill; if it so continues;

(c) whether the Chairman and Managing Director of National Textile Corporation is functioning as Chairman and acting Managing Director of Swadesh Polytex Limited in violation of Sections 269 and 316 of the Companies Act, 1956; if so, what are the reasons therefor; and

(d) what follow-up action is taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) Yes, Sir. The matter is being looked into.

(b) This is not a Govt. Company and Govt. does, therefore, have any information except the published documents of the Company.

(c) and (d) CMO, NTC has not been appointed as Managing Director of this Company. The current arrangement it temporary pending the appointment of a full time Managing Director.

Long term Fiscal policy

2455. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Finance Ministry had prepared a document titled Long Term Fiscal Policy in 1986 and had decided to put it in action;

(b) whether the suggestions contained in the document have been implemented; and

(c) what is the present status of the document?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The Long Term Fiscal Policy (LTFP) document prepared by the Finance Ministry was laid in the Parliament in December, 1985. Several of the important tax policy intensions announced in the LTFP have since been implemented through successive Budgets.

DESU Scales to NDMC ministerial staff

2456. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the NDMC has agreed to grant DESU scales to its ministerial staff in accordance with the Supreme Court judgement dated the 7th August, 1987;

(b) whether the NDMC had agreed to grant the DESU scales to 18 categories of NDMC employees including HA/Accountants;

(c) whether the benefits to SS scales have been granted to the 496 petitioners only;

(d) whether the Accountants (SSSA) who were among the petitioners to the Supreme Court judgement have been denied the benefit of the judgement; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) In accordance with the judgement of Supreme